(ग) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों (स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के सिवाय) में विभिन्न संवर्गों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार था :—

संवर्ग	कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	महिला कर्मचारियों की प्रतिशतता
अधिकारी	237719	11010	4.63
लिपिक	447170	87067	19.47
अधीनस्थ स्टाफ	176777	7340	4.15
सफाई कर्मचारी (अंशकालिक सफाई कर्मचारियों सहित)	30050	9985	33.23

31-3-1994 की स्थिति के अनुसार, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र में, सभी ग्रेडों में 8001 कर्मचारियों में से महिला कर्मचारियों की संख्या 716 (8.95%) थी।

जाली शेयर प्रमाण-पत्रों का प्रचलन

218. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :**

चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जाली शेयर प्रमाण-पत्रों के प्रचलन में बढ़ोत्तरी के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है , और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री (एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) देश में जाली शेयर प्रमाणपत्रों के परिचालन की सीमा के बारे में कोई मूल्यांकन करना संभव नहीं है ।

(ग) सरकार और स्टॉक एक्सचेंजों जैसे अन्य संबंधित अभिकरण जाली शेयर प्रमाणपत्रों के परिचालन पर नियंत्रण रखने के लिए निरन्तर सतर्कता बरत रहे हैं ।

(घ) ऊपर (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को हो रहा घाटा

219. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को किन-किन कारणों से घाटा हो रहा है ;

(ख) क्या इन कारणों को दूर किया जा सकता है ;

(ग) यदि हां, तो इस घाटे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ;

(घ) क्या इस क्षेत्र के कर्मचारियों की लापरवाही और उनके कदाचार के कारण भी उक्त घाटा हो रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की दलील और उसकी प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के घाटों के लिए जिम्मेदार कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं : अनुपयोज्य आस्तियों (एन०पी०ए०) के उच्च स्तर, तुलनात्मक दृष्टि से कम उत्पादकता, लेनदेन की मात्रा को देखते हुए अपर्याप्त तकनीक और कानूनी प्रणाली के द्वारा वसूली में देरी ।

(ख) और (ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों से उनके तन्त्र और ऋण मूल्यांकन को मजबूत करने, अग्रिमों का प्रभावी पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने, अपने प्रधान कार्यालयों में वसूली कक्ष स्थापित करने और उत्पादकता के स्तर में सुधार करने के लिए जोर देते रहे हैं । पूंजी पर्याप्तता आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण मानदण्डों को लागू किया गया है। बैंकों की देय राशियों की वसूली के लिए सरकार ने ऋण वसूली प्राधिकरणों की स्थापना भी की है ।

(घ) और (ङ) कुछ कर्मचारियों की लापरवाही और कदाचारों से भी बैंकों को हानियां होती हैं । बैंक निवारक और दण्डात्मक उपाय करते हैं ।

आयकर विभाग द्वारा किया गया सर्वेक्षण

220. **श्री आस मोहम्मद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग के सर्वेक्षण खंड ने दिल्ली के व्यापारियों, आभूषण विक्रेताओं और उद्योगपतियों द्वारा किये गये कर अपवंचन के अनेकों मामलों का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) इस संबंध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :(क) से (ग) धारा 133 क(1) के तहत किसी आयकर प्राधिकारी को उन परिसरों का सर्वेक्षण करने की अनुमति है जहां पर कोई कारोबार अथवा व्यवसाय किया जाता हो। ये सर्वेक्षण मुख्यतः छिपाई गई आय का पता लगाने के लिए किए जाते है। चालू वित्तीय वर्ष में, दिल्ली स्थित कर निर्धारण शाखा ने 234 सर्वेक्षण किए हैं। इन सर्वेक्षणों में लगभग 11.18 करोड़ रुपये की छिपाई गई आय का पता लगाया गया है । छिपाई गई आय मुख्यतः गत वर्ष 1994–95 से संगत कर-निर्धारण वर्ष 1995–96 से संबंधित है । इन सर्वेक्षणों के अंतर्गत शामिल कर-निर्धारितियों से लगभग 2.60 करोड़ रुपये की कर राशि वसूल की गई है ।

सहकारी बैंकों का पूंजी आधार

221. **श्री राघवजी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक और ग्रामीण बैंकों के समान सहकारी बैंकों के पूंजी आधार को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है: और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने पर विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :(क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विपरीत जहां केन्द्रीय सरकार शेयर पूंजी में प्रत्यक्ष रूप से अंशदान करती है राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों की शेयरधारिता में उनके सदस्यों और राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है. कुछ सीमा तक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिला और राज्य स्तरीय सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों की सहायता करता है ।